मध्यप्रदेश में गण को मजबूत करता एम व ई-तंत्र

❑ सरमन नगेले

अक्सर कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे प्रभावशाली लोग उठा लेते हैं जिनकी पहुंच इनसे जुड़ी सुचनाओं तक होती है। ऐसे में आमजन व गांव की आवाज अपनी पहुंच, अपने उपकरणों और अपने अनुप्रयोगों के मामले और सूचना का लोकतंत्रीकरण करने में लगी है, नई संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानि मोबाइल और ई-गवर्नेंस का फैलता हुआ दायरा....संभवतः यही नयी तकनीक को क्रांतिकारी रूप दे रही है। यही तकनीक है जो गण को ई और मोबाइल तंत्र के जरिये सशक्त बना रही है। म.प्र. के गणों को एक सूत्र में पिरोने की एक बड़ी क्रांति नई तकनीक के जरिए हो रही है।

वैसे छोटी-मोटी बातों के लिए भी कागज पर लिखित लेखा-जोखा और मानवीय परिश्रम पर ज्यादा आधारित रही भारतीय जीवन शैली में डिजिटल उत्पादों के प्रयोग ने अनेक परिवर्तन किये हैं। नगरों और छोटे शहरों के निवासियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी थोड़ी-बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन गाँवों की स्थिति दयनीय थी। अब डिजिटल उत्पादों, इंटरनेट तथा आईसीटी की पहुंच और प्रयोग के चलते गाँव और शहर के बीच का अंतर लुप्त हो गया। समाज के सभी वर्गों की जनता के लिए आधुनिक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण सभी वर्गों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ प्रगति दीख पड़ती है।

"म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वैसे ई-शासन का संबंध सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना टेक्नालॉजी व बुनियादी ढांचे से नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के सुधारों को साकार करने का एक शानदार अवसर है। राज्य में लोक सेवा और एम व ई गवर्नेंस के तालमेल के साथ इसकी बुनियाद व सरकार के कामकाज को गुणदोष के आधार पर न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। साथ ही अवार्ड भी मिल रहे हैं। प्रदेश में हो रहे आईसीटी कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिये प्रत्येक वर्ष 6 जून को आई.टी. दिवस मनाया जा रहा है।"

आईसीटी के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ये वे परिवर्तन हैं जिनके चलते मध्यप्रदेश का गण दिन-प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है।

गण को कैसे मजबूत करता ई और एम तंत्रः एक नजर

"कल्याणकारी राज्य के लिए विकास और सुशासन दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके आधार पर उन्नति और प्रगति का मार्ग बनता

है, विकास के लिए सुशासन पहली शर्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए मध्यप्रदेश में नया इतिहास लिखने का संकल्प दोहराया है। सुशासन के लिए सबसे जरूरी है उपलब्ध तकनीकी और प्रौद्योगिकी का सकारात्मक उपयोग। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में काफी समय पहले अपने कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य में सुशासन तीव्र गति से आकार भी ले रहा है।"

म.प्र. में एम व ई-गवर्नेंस

अधोसंरचना - आईटी पार्क (एसईजेड-विशेष प्रक्षेत्र जोन), "एमपी स्वान" एमपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ब्राडबैंड कनेक्टीविटी की दिशा में ब्लाक स्तर तक पूरे राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। स्टेट डाटा सेंटर, इन्दौर, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिलों में ई-डिस्ट्रिक परियोजना, स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिये भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए प्रयास तेज हो गये हैं। साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर के संबंध में 22 और 23 अक्टूबर, 2010 को खजुराहो में संपन्न हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में एमओयू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा नेशनल ई-गवर्नेन्स परियोजना के तहत प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करने का निर्णय है। योजना के क्रियान्वयन के प्रथम चरण में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, इन्दौर तथा सागर जिलों का चयन किया गया है। आवश्यकताओं का आकलन पूरा कर साफ्टवेयर का निर्माण किया जा चुका है। ई-डिस्ट्रिक्ट के जरिए आमजन को शीघ्र अनेक सुविधायें राज्य शासन मुहैया करायेगा। मंत्रालय में स्थापित लेन को अपग्रेड किया जाकर गीगाबाईट लेन की स्थापना की गई है। भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क एमपी स्वान अधोसंरचना के लिये राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 340 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

जी2जी, के अंतर्गत मंत्रालय का कम्प्यूटरीकरण, समाधान ऑनलाइन के अलावा मंत्रालय से संबंधित ई-गवर्नेंस की परियोजनाएं। मुख्यमंत्री का मॉनीटरिंग व मुख्य सचिव का मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम आदि।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माह के प्रथम मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा समाधान ऑनलाइन के जरिए आमजन की समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रशासन को चुस्त, दुरुस्त व पारदर्शी बनाने के लिये समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सूचना-प्रौद्योगिकी के नये-नये अनुप्रयोगों को लगातार अपनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा इस श्रृंखला की नवीन कड़ी है। देश में वीडियों कांफ्रेंसिंग के उपयोग के मामले में मध्यप्रदेश शासन प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक उपयोग के लिये इसे लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस में भी स्थान मिला हुआ है।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए प्रदेश में 9232 कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की जाना है। अभी तक 6000 से अधिक स्थापित हो चुके हैं। ई-गुमठियों के जरिए 16 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन केन्द्रों द्वारा ई-प्रशासन को सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों को कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से उच्च स्तरीय वीडियो, विभिन्न डाटा, ई-गवर्नेन्स सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य,

मनोरंजन आदि की जानकारी उपलब्ध कराना है।

म.प्र. के गृह विभाग ने आम जनता को विभागीय पत्र एवं नस्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिटीजन सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। गृह विभाग से 10 महत्वपूर्ण सेवाओं से संबंधित आवेदनों की जानकारी इंटरनेट पर अब http://www.mp.gov.in/home/ पर उपलब्ध रहेगी। किसानों के लिये एमपीकृषि डॉट ओआरजी तथा मीडिया व आमजन के लिए जनसंपर्क संचालनालय द्वारा संचालित एमपीइंफो डॉट ओआरजी शासन-प्रशासन से संबंधित सूचनाओं व चित्रों को उपलब्ध करा रही है। मध्यप्रदेश के वन विभाग में वन और वन्यजीव के प्रबंधन के लिये मंत्रा फार गुड गवर्नेंस के तहत मोबाइल आधारित 7 एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। परिवहन और वाणिज्यिक कर विभाग के अलावा अन्य विभागों में आई.टी. को अपनाया गया है। कुछ जिलों ने ई-गवर्नेंस व एम-गवर्नेंस के क्षेत्र में भी अभिनव कार्य किये हैं।

राज्य शासन ने संयुक्त उपक्रम के तहत www.mponline.gov.in नामक पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल 160 प्रकार की सेवाएं दे रहा है। राज्य के 30 विभागों, 6 विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थाओं से संबंधित 62 लाख से अधिक सेवाएं पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।

कॉल सेन्टर - मध्यप्रदेश सरकार ने आमजन की शिकायतों को प्राप्त कर उनका निराकरण करने के लिये एक अभिनव मोबाइल, फोन टेक्नालॉजी आधारित टेली समाधान सेवा आरंभ की है। इस सेवा का लाभ लेने के लिये सरकार ने जनता के लिये एक टोल फ्री नम्बर 155343 रखा है। टेली समाधान में 16 विभागों से संबंधित न केवल शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन उनका समाधान भी हो रहा है।

ई-टेण्डर - राज्य में शासकीय निविदाओं में इलेक्ट्रानिक टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है। ई-टेण्डर के माध्यम से अभी तक रुपये 451570.60 लाख रुपये, 1823 से अधिक नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, एमपीएसईडीसी और विद्युत वितरण कंपनी आदि के टेण्डर जारी किये जा चुके हैं।

स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम एवं कैपेसिटी बिल्डिंग- राज्य में स्टेट ई-गवर्नेंस टीम का गठन किया गया है। मिशन मोड परियोजना के विभागों के लिये परियोजना प्रतिवेदन का कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एनआईएसजी के माध्यम से आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यों में राज्य द्वारा हिस्सा लिया गया है।

स्टेट डाटा सेंटर - इस परियोजना के तहत प्रदेश में पूर्णतः एक नया भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। अरेरा हिल्स में नया भवन लगभग पूर्ण होने की ओर है।

एसएसडीजी स्टेट पोर्टल- इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका हैं।

अवार्ड - मध्यप्रदेश को लगभग 20 से अधिक ई और एम गवर्नेंस के अवार्ड मिल चुके हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग तथा आईटी मंत्रालय भारत सरकार आईटी क्षेत्र का प्रतिष्ठित मंथन अवार्ड, आईटी के उपयोग के लिए इंडिया टेक एक्सीलेंस अवार्ड, सीएसआई निहीलेण्ट अवार्ड, देश की आईटी जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका डाटा क्वेस्ट का ई-गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड, नैसकाम सीएनबीसी टीवी 18, आईटी यूजर्स अवार्ड, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का वेब रत्न और साउथ एशिया के पहले मोबाइल गवर्नेंस अवार्ड से मध्यप्रदेश नवाजा गया है।

कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में बीते वर्षो में शासन-प्रशासन एवं निजी स्तर पर अनेक अभिनव कार्य हुए हैं। ई और एम गवर्नेंस के विकल्प ने प्रदेश की जनता को ऐसे अवसर मुहैया करा दिये हैं जिनके चलते आमजन न केवल सशक्त हो रहा है, वरन् अपनी इच्छाओं एवं महत्वाकांक्षाओं को साकार होता भी देख रहा है।

(लेखक पत्रकार हैं।)